



भारत का राजपत्र The Gazette of India

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 298]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 20, 2013/अग्रहायण 29, 1935

No. 298]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 20, 2013/AGRAHAYANA 29, 1935

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 2013

विषय : चीन जन. गण. के मूल के या वहां से निर्यातित शीट ग्लास के आयातों के संबंध में पाटनरोधी शुल्क जांच की शुरुआत।

सं. 14/22/2013-डीजीएडी.—मैसर्स भारत ग्लास ट्यूब लिमिटेड ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं का अभिज्ञान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "पाटनरोधी नियमावली" कहा गया है), के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे प्राधिकारी कहा गया है), के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें चीन जन. गण. (जिन्हें आगे संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के या वहां से निर्यातित शीट ग्लास (जिसे आगे संबद्ध वस्तु कहा गया है) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरुआत करने का अनुरोध किया गया है।

विचाराधीन उत्पाद

2. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित शीट ग्लास हैं, इसका उत्पादन क्षैतिज लहर का प्रयोग करके किया जाता है। सीसे को गली धातु को मुक्त सतह से सीधे लिया जाता है और शीट के किनारों को घूमते हुए आकारों का प्रयोग करके सीसे को ऊपर लेजाकर स्थिर किया जाता है। गला हुआ सीसा लगभग 1000 एमएम की ऊंचाई पर लगी वर्टीकल ड्राइंग मशीनों से सीसे की भट्टी से गुजरता है जहां से बने हुए कांच को क्षैतिज प्रवाह के द्वारा सीसे की शीट में परिवर्तित किया जाता है। शीट बन जाने पर उसे पॉलिश किए गए धात्विक रोल पर मोड़ा जाता है और क्षैतिज रूप से लहर में ले जाया जाता है। फ्लोट ग्लास, फिगर्ड और वायरड ग्लास विचाराधीन उत्पाद के दायरे में शामिल नहीं हैं।

3. विचाराधीन उत्पाद को अध्याय 70 में "ग्लास और ग्लासवेयर" शीर्ष के अंतर्गत और आगे 7004.20 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। 8 अंकीय स्तर पर वर्गीकरण 70042011 और 70042019 है। यह वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर किसी भी तरह से बाध्यकारी नहीं है।

5328 GI/2013

(1)

समान वस्तु

4. याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि भारत में पाटित की जा रही संबद्ध वस्तु और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु समान है। पाटित आयातों और घरेलू रूप से उत्पादित संबद्ध वस्तु के तकनीकी विनिर्देशनों, कार्यों और अंतिम प्रयोगों के बीच कोई अंतर

नहीं है। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इसलिए पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत इन्हें 'समान वस्तु' माना जाना चाहिए। अतः वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ भारत में आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और संबद्ध देश से आयात की जा रही संबद्ध वस्तु को 'समान वस्तु' माना जा रहा है।

घरेलू उद्योग और उसकी योग्यता

5. यह याचिका मैसर्स भारत ग्लास ट्यूब लिमिटेड, अंकलेश्वर द्वारा दायर की गई है और उन्होंने यह दावा किया है कि वे विचाराधीन उत्पाद के एकमात्र उत्पादक हैं। अतः प्राधिकारी निर्धारित करते हैं कि आवेदक नियम 2 (ख) के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग है और यह आवेदन संबंधित नियमावली के नियम 5 (3) के अनुसार योग्यता संबंधी मापदंड को पूरा करता है।

संबद्ध देश

6. वर्तमान जांच में शामिल देश चीन जन. गण. है।

सामान्य मूल्य

7. याचिकाकर्ताओं ने बताया है कि चीन जन. गण. को गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना जाना चाहिए और सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमावली के अनुबंध—I के पैरा 7 के अनुसार किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता ने यह बताते हुए भारत में विधिवत रूप से समायोजित उत्पादन लागत के आधार पर संबद्ध वस्तु की सामान्य मूल्य का दावा किया है कि बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश में लागत या कीमत से संबंधित सूचना उपलब्ध नहीं है। प्राधिकारी ने प्रथम दृष्टया इस जांच शुरुआत के प्रयोजनार्थ आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराए गए परिकलित मूल्य के आधार पर संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु के सामान्य मूल्य को माना है।

निर्यात कीमत

8. आवेदक ने डीजीसीआईएस से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर निर्यात कीमत का दावा किया है। निवल निर्यात कीमत ज्ञात करने के लिए समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, अंतरदेशीय परिवहन, कमीशन, बैंक प्रभारों, पत्तन सम्भलाई और पत्तन प्रभारों आदि के लिए कीमत समायोजनों की अनुमति दी गई है।

पाटन मार्जिन

9. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखाना द्वार स्तर पर की गई है जिससे प्रथम दृष्टया संबद्ध देश के संबंध में भारी पाटन मार्जिन का पता चलता है। इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य कारखाना द्वार निर्यात कीमत से काफी अधिक है जिससे प्रथम दृष्टया पता चलता है कि संबद्ध वस्तुओं का संबद्ध देश से निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में पाटन किया जा रहा है। इस प्रकार पाटन मार्जिनों का अनुमान न्यूनतम सीमा से अधिक पर लगाया गया है।

क्षति और कारणात्मक संबंध

10. घरेलू उद्योग को हुई क्षति का आकलन करने के लिए याचिकाकर्ताओं की सूचना पर विचार किया गया है। याचिकाकर्ताओं ने समग्र रूप से और भारत में उत्पादन और खपत की दृष्टि से पाटित आयातों की बढ़ी हुई मात्रा, भारी कीमत कटौती और कम कीमत पर बिक्री तथा इसके परिणामस्वरूप उत्पादन, क्षमता उपयोग, घरेलू बिक्री मात्रा, वस्तु सूची, बाजार हिस्से, लाभ, नियोजित पूंजी पर आय और नगद प्रवाह पर प्रतिकूल परिणामी प्रभाव के रूप में कथित पाटन के परिणामस्वरूप हुई क्षति के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग द्वारा क्षति उठाए जाने के पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं जिससे पाटनरोधी जांच की शुरुआत करना न्यायोचित है।

जांच की शुरुआत

11. प्राधिकारी प्रथम दृष्टया पाते हैं कि संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन, घरेलू उद्योग को हुई 'क्षति' के पर्याप्त साक्ष्य हैं और कथित पाटन तथा 'क्षति' के बीच पाटनरोधी जांच की शुरुआत को उचित ठहराने वाला कारणात्मक संबंध मौजूद है इसलिए प्राधिकारी एतद्वारा पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के अनुसार कथित पाटन और घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति की जांच करने और कथित पाटन की मौजूदगी उसकी मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने और ऐसे पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश करने जिसे यदि लगाया जाए तो घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, की सिफारिश करने के लिए पाटनरोधी जांच की शुरुआत करते हैं।

जांच अवधि

12. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच अवधि (पीओआई) 1 जुलाई, 2012 से 30 जून, 2013 (12 माह) तक की है। तथापि, क्षति संबंधी जांच के प्रयोजनार्थ इस अवधि में पिछले तीन वर्षों अर्थात् अप्रैल 2010-मार्च, 2011, अप्रैल 2011-मार्च, 2012, अप्रैल 2012-मार्च, 2013 और जांच अवधि (पीओआई) शामिल होगी।

सूचना प्रस्तुत करना

13. संबद्ध देश में ज्ञात निर्यातकों, उनके दूतावासों के जरिए संबद्ध देशों की सरकारों, उत्पाद से संबंधित समझे जाने वाले भारत में ज्ञात आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को निर्धारित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने और निम्नलिखित पते पर प्राधिकारी को अपने विचारों से अवगत कराने के लिए अलग से लिखा जा रहा है। कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी जांच से संगत सूचना संबंधी कोई अनुरोध नीचे दी गई समय सीमा के भीतर कर सकता है और निम्नांकित पते पर भेज सकता है :

निर्दिष्ट प्राधिकारी
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय
वाणिज्य विभाग,
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,
कमरा सं. 240, उद्योग भवन,
नई दिल्ली-110011

समय-सीमा

14. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस (40) दिनों से पूर्व उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास लिखित में पहुंच जाना चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी है तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमों के अनुसार, "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

15. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस जांच की शुरुआत की तारीख से 40 दिनों के भीतर वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और प्रश्नावली के अपने उत्तर दायर करें तथा पाटनरोधी उपाय जारी रखने की जरूरत अथवा अन्यथा के बारे में घरेलू उद्योग के आवेदन पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करें।

गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

16. यदि प्रश्नावली के उत्तर/अनुरोधों के किसी भाग के बारे में गोपनीयता का दावा किया जाता है तो उसे दो अलग-अलग सैटों (क) गोपनीय रूप में अंकित (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि) और (ख) अगोपनीय रूप में अंकित दूसरा सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि) में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। प्रस्तुत की गई समस्त सूचना पर प्रत्येक पृष्ठ के सबसे ऊपर स्पष्ट रूप से "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए।

17. किसी गोपनीय अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। समस्त हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय रूपांतरण की दो (2) प्रतियां और अगोपनीय रूपांतरण की पांच (5) प्रतियां प्रस्तुत की जानी चाहिए।

18. गोपनीय रूप में दावा की गई सूचना हेतु सूचना प्रदाता के लिए यह अपेक्षित है कि वह प्रदान की गई सूचना के साथ इस आशय के यथोचित कारण का एक विवरण उपलब्ध कराए कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता और/अथवा ऐसी सूचना का सारांश क्यों संभव नहीं है।

19. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई/सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है; तो प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों संभव नहीं है।

20. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

21. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी

अनुरोध को प्राधिकारी रिकॉर्ड में नहीं ले सकते हैं। संतुष्ट होने और प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत को स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

22. नियम 6(7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

असहयोग

23. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

जे. एस. दीपक, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 20th December, 2013

Subject : Initiation of Anti-Dumping Duty investigation concerning imports of Sheet Glass originating in or exported from China PR

No.14/22/2013-DGAD.—M/s Bharat Glass Tube Limited, has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the Act) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped articles and for Determination of injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter referred to as the AD Rules) for initiation of Anti-Dumping Duty investigation concerning imports of Sheet Glass (hereinafter also referred to as the subject goods) originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as the subject country).

Product under Consideration

2. The product under consideration in the present investigation is Sheet Glass, originating in or exported from China PR. It is produced by using horizontallylehr. The glass is taken directly from the free surface of the melt and the edges of the sheet are stabilized by driving the glass upward using rotating bodies. The molten glass passes from the glass furnace to a vertical drawing machine to a height of about 1000 MM from where the formed glass is converted in to glass sheet by horizontal flow. Once the sheet is formed it is bent over a polished metal roll and carried away horizontally into a lehr. Float glass, Figured and Wired glass are not covered within the scope of Product under Consideration.

3. Product under Consideration is classified under the heading "Glass and Glassware" in Chapter 70 and further under 7004.20. The classification at 8 digit level is 70042011 and 70042019. The classification, is only indicative and in no way binding on the scope of the present investigation.

Like Article

4. Petitioner has claimed that the subject goods, which are being dumped into India, are identical to the goods produced by the domestic industry. There are no differences either in the technical specifications, functions or end-uses of the dumped imports and the domestically produced subject goods. The two are technically and commercially substitutable and hence should be treated as 'like articles' under the Anti Dumping Rules. Therefore for the purpose of present investigation the subject goods produced by the applicant in India are being treated as like article to the subject goods being imported from subject country

Domestic Industry & 'Standing'

5. The Application has been filed by M/s Bharat Glass Tube Limited Ankaleshwar , who has claimed that they are the sole producer of the product under consideration. The Authority, therefore, determines that the applicant constitutes domestic industry within the meaning of the Rule 2 (b) and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5 (3) of the Rules supra..

Subject Country

6. The country involved in the present investigation is China PR .

Normal Value

7. The Petitioners have submitted that China PR should be treated as a non-market economy and the normal value should be determined in accordance with para-7 of Annexure-I to the Rules. The petitioners have claimed normal value of subject goods on the basis of cost of production in India, duly adjusted stating that information relating to cost or price in a market economy third country is not available. The Authority has prima-facie considered the normal value of subject goods in subject country on the basis of constructed values as made available by the applicants for the purpose of this initiation.

Export Price

8. The applicant has claimed export prices on the basis of data obtained from DGCI&S. Price adjustments have been allowed on account of Ocean freight, marine insurance, inland transportation, commission, bank charges, port handling and port charges etc. to arrive at the net export price.

Dumping Margin

9. Normal value and export price have been compared at ex-factory level, which shows prima facie significant dumping margin in respect of the subject country. There is sufficient prima facie evidence that the normal value of the subject goods in the subject country are significantly higher than the ex-factory export price, indicating, prima facie, that the subject goods are being dumped into the Indian market by the exporters from the subject country. The dumping margins so estimated are above de minimus.

Injury and Causal Link

10. Information of petitioners has been considered for assessment of injury to the domestic industry. The Petitioners have furnished evidence regarding the 'injury' having taken place as a result of the alleged dumping in the form of increased volume of dumped imports in absolute terms and in relation to production and consumption in India, significant price undercutting and price depression and consequent significant adverse impact in terms of production, capacity utilization, domestic sales volumes, inventories, market share, profits, return on capital employed, and cash flow for the domestic industry. There is sufficient evidence of the 'injury' being suffered by the domestic industry caused by dumped imports from subject country to justify initiation of an antidumping investigation.

Initiation of Investigation

11. The Authority finds prima facie that sufficient evidence of dumping of the subject goods originating in or exported from the subject country, 'injury' to the domestic industry and causal link between the alleged dumping and 'injury' exist to justify initiation of an anti-dumping investigation; the Authority hereby initiates an investigation into the alleged dumping, and consequent injury to the domestic industry in terms of the Rules 5 of the AD Rules, to determine the existence, degree and effect of alleged dumping and to recommend the amount of antidumping duty, which if levied would be adequate to remove the 'injury' to the domestic industry.

Period of Investigation

12. The period of investigation (POI) for the purpose of present investigation is 1st July 2012 to 30th June 2013 (12 months). However, for the purpose of injury investigation, the period will cover the data of previous three years, i.e. April 2010 to March 2011, April 2011 to March 2012, April 2012 to March-2013 and the period of investigation (POI).

Submission of information

13. The known exporters in the subject country and their Governments through their Embassies, importers and users in India known to be concerned and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all information relevant in the form and manner prescribed. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation within the time-limit set out below and write to:

The Designated Authority,
Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties,
Ministry of Commerce & Industry,

Department of Commerce,
Room No 240 , Udyog Bhawan,
New Delhi -110107

Time limit

14. Any information relating to this investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the above address not later than 40 days from the date of this notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the 'facts available' on record in accordance with the AD Rules.

15. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire's responses and offer their comments to the domestic industry's application regarding the need to impose anti-dumping measures within 40 days from the date of initiation of this investigation.

Submission of Information on Non-Confidential basis

16. In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire's response/ submissions, the same must be submitted in two separate sets (a) marked as Confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as Non-Confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either "confidential" or "non-confidential" at the top of each page.

17. Information supplied without any mark shall be treated as non-confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Two (2) copies each of the confidential version and the non-confidential version must be submitted.

18. For information claimed as confidential; the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible.

19. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out / summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible of summary; a statement of reasons why summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.

20. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

21. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Authority. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information

Inspection of Public File

22. In terms of rule 6(7) any interested party may inspect the public file containing non-confidential versions of the evidence submitted by other interested parties.

Non-cooperation

23. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Governments as deemed fit.

J. S. DEEPAK, Designated Authority

